

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश।

प्रदेश में दिनांक 01-01-08 से वैट व्यवस्था लागू की गयी है। वैट अधिनियम की धारा-13 के अन्तर्गत व्यापारियों द्वारा आई०टी०सी० क्लेम किये जाने की व्यवस्था है। वैट अधिनियम में व्यापारियों को दी गयी उक्त व्यवस्था के क्रम में व्यापारी द्वारा क्लेम किये इनपुट टैक्स का सत्यापन भी अति आवश्यक है। अतः व्यापारियों द्वारा दाखिल किये गये मासिक / त्रैमासिक रूपपत्रों की सतत समीक्षा एवं सन्निरीक्षा करनिर्धारण अधिकारियों द्वारा किये जाने के संबंध में मुख्यालय द्वारा परिपत्र संख्या-755 दिनांक 12-10-2008, पत्र संख्या-168 दिनांक 20-04-2009, पत्र संख्या-1593 दिनांक 18-09-2009, पत्र संख्या-778 दिनांक 30-07-2013 एवं पत्र संख्या-1528 दिनांक 04-12-2013 के माध्यम से निर्देश निर्गत किये गये हैं ताकि व्यापारियों द्वारा आई०टी०सी० के संबंध में वैट अधिनियम में दी गयी व्यवस्था का अनुचित एवं त्रुटिपूर्ण लाभ न लिया जा सके परन्तु फील्ड के अधिकारियों द्वारा अभी भी दाखिल रूपपत्रों की शत प्रतिशत समीक्षा नहीं की जा रही है।

मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि वैट प्राविधानों के अन्तर्गत दाखिल किये गये आन लाइन मासिक रूपपत्रों में कतिपय व्यापारियों द्वारा नान वैट गुड्स पर चुकाये गये कर की नियम विरुद्ध आई०टी०सी० क्लेम की जा रही है। उदाहरण स्वरूप एक व्यापारी द्वारा नेचुरल गैस अदर दैन सी०एन०जी० की खरीद को दाखिल किये गये अपने रूपपत्र-24 के अनुलग्नक-ए में दर्शित करते हुये उसकी खरीद पर दिये गये कर को आई०टी०सी० के रूप में क्लेम किया गया है, जबकि नेचुरल गैस अदर दैन सी०एन०जी० वैट अधिनियम की सूची-4 में अधिसूचित है जो कि नान वैट गुड्स की श्रेणी में है। इस प्रकार उक्त वस्तु की खरीद पर वैट प्राविधानों के अधीन आई०टी०सी० अनुमन्य नहीं है फिर भी व्यापारी द्वारा जानबूझ कर नान वैट गुड्स की खरीद को अनुलग्नक-ए में दर्शित कर आई०टी०सी० क्लेम कर करापवंचन का प्रयास किया गया है। उक्त दृष्टान्त से स्पष्ट है कि मुख्यालय द्वारा फील्ड के अधिकारियों को रूपपत्रों की सतत समीक्षा एवं सन्निरीक्षा किये जाने के स्पष्ट निर्देश दिये जाने के बावजूद भी जानबूझकर व्यापारियों द्वारा त्रुटिपूर्ण आई०टी०सी० क्लेम किये जाने के प्रकरण सामने आ रहे हैं। उपरोक्त प्रवृत्ति पर तत्काल अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता है। रूपपत्रों की शतप्रतिशत नियमित समीक्षा एवं सन्निरीक्षा के संबंध में निर्गत निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन कराया जाना नितान्त अनिवार्य है।

वर्तमान समय में ई-रिटर्न दाखिल करने वालों व्यापारियों की आई०टी०सी० सत्यापन की आन लाइन व्यवस्था कर दी गयी है। इसके साथ ही अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों के अन्तर्गत स्टॉक ट्रांसफर, क्रय मूल्य से कम बिक्री, धारा-7(सी) माल वापसी, माल के निजी प्रयोग, डेमेज आदि का परीक्षण करके आर०आई०टी०सी० की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। इसके लिये आन लाइन / मैनुवली दाखिल किये गये रूपपत्रों की नियमित समीक्षा एवं सन्निरीक्षा किया जाना आवश्यक है।

अतः अपने अधीनस्थ करनिर्धारण अधिकारियों को इस आशय के निर्देश दे कि व्यापारियों द्वारा दाखिल रूपपत्र-24 की नियमित समीक्षा करते हुये वैट प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें। भविष्य में इस प्रकार के मामलों प्रकाश में आने पर उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाते हुये कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

M4  
16.1.2015  
(मृत्युंजय कुमार नारायण)  
कमिश्नर, वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश।